

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

विजाड़न इंडिया

निर्मांक और देवाक अभियक्ति
लखनऊ से प्रकाशित

EMAIL: sheelshukla100@gmail.com

वर्ष: 14 अंक: 82

लखनऊ,

गुरुवार 07 नवंबर 2024

मूल्य: 02 रुपये

पृष्ठ- 08

आतंकियों का होगा जड़ से सफाया! आतंकवाद विरोधी सम्मेलन को संबोधित करेंगे अमित शाह

एजेंसी।

केंद्रीय गृह मंत्री और संघर्षिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन-2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से उत्थन होने वाले खतरों पर विचार-विमर्श के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में वार्षिक सम्मेलन परिचालन बलों के लिए एक



बैठक बिंदु के रूप में उभरा है राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से उत्थन होने वाले खतरों पर विचार-विमर्श के लिए आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवादी एजेंसियों को साझा करने, उभरती प्रौद्योगिकियों से संबोधित चुनौतियों और अवसरों, अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग और रणनीतियों पुलिस बलों और आतंकवाद प्रौद्योगिकी आदि कारी और कानून, फोरेंसिक, प्रौद्योगिकी आदि जीसे संबोधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। पिछले साल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस बलों और आतंकवाद प्रौद्योगिकी एजेंसियों से ऐसा घूर्ह दृष्टिकोण अपनाने को कहा था ताकि कोई नया आतंकवादी समूह न बन सके।

भविष्य की नीति निर्माण के लिए ठोस इनपुट प्रस्तुत करना है। दो विवरीय सम्मेलन में विचार-विमर्श पुलिस अधिकारी, आतंकवाद विरोधी जांच में अभियोजन और कानूनी ढांचे को विकसित करने, अनुभवों और अच्छी प्रथाओं को साझा करने, उभरती प्रौद्योगिकियों से संबोधित चुनौतियों और अवसरों, अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग और रणनीतियों पुलिस बलों और आतंकवाद प्रौद्योगिकी एजेंसियों से ऐसा घूर्ह दृष्टिकोण अपनाने को कहा था ताकि कोई नया आतंकवादी समूह न बन सके।

एक है तो सेफ है... बंटेगे तो कटेगे के बाद सीएम योगी का नगा नारा,

महाराष्ट्र में एमवीए को बताया महाअनाड़ी गठबंधन

भारत रहना चाहिए और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए। उन्होंने लोगों से

आगरा गया था।

आगरा में जब मैं

निरीक्षण कर रहा

था तो मुझे बताया

गया कि वहाँ एक

मुगल संग्राहलय

है।

मैंने कहा कि मुगल का

भारत और आगरा

से क्या संबंध है?



कहा कि मुझे याद है कि जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तब मैं आगरा गया था। आगरा में जब मैं निरीक्षण कर रहा था तो मुझे बताया गया कि वहाँ एक मुगल संग्राहलय है। मैंने कहा कि मुगल का भारत और आगरा से क्या संबंध है?

अपील की बंटिए मत! क्योंकि जब भी बंटे थे तो करे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। वही, अमरावती में योगी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराजी गठबंधन है। उन्होंने सचाल करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस ने कभी इमानदारी से भारत और भारतीयता के बारे में सोचा? योगी ने साफ तौर पर कहा कि सच्चाएं तो आएंगी-जाएंगी। लेकिन हमारा

हमने कहा भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है।

इस स्मृतियम का नाम बदलो।

यह संग्राहलय मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक बनना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर

कहा कि क्या कांग्रेस ने उसे कालखंड में जब भी रंगजे बैंडर जाए, बारे बदल आक्रांता भारत में शासन कर रहा था, तब उन्होंने उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने आगे

सुनी है, लेकिन बंटना नहीं है।

लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष ने जूँ

फैलाया

एजेंसी।

बारामती। अजित पवार ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक दलों को लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष द्वारा संविधान के संबंध में फैलाए गए जूँठे विमर्श का खामिया भुगतना पड़ा। हालांकि, अजित ने कहा कि सरकार की जन-केंद्रित योजनाओं की वजह से महायुति के महाराष्ट्र में सत्ता में बने रहने के लिए अनुकूल माहौल है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री गठबंधन पर विपक्ष पवार ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक दलों को लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष द्वारा संविधान के संबंध में फैलाए गए जूँठे विमर्श का खामिया भुगतना पड़ा। हालांकि, अजित ने कहा कि सरकार की जन-केंद्रित योजनाओं की वजह से महायुति के महाराष्ट्र में सत्ता में बने रहने के लिए अनुकूल माहौल है। जबकि विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (एमपीए) ऐसे वाद करता है, जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने विश्वास जाता था कि वह बारामती विधानसभा सीट पर एक बार फिर जीत दर्ज करेंगे। उपमुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र बारामती में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का घोषणापत्र जारी करने के बाद बोल रहे थे।

जनता की नजरों में कौन असली शिवसेना, जानिए वया कहते हैं सियासी समीकरण

एजेंसी।

शिवसेना के विभाजन के बाद महाराष्ट्र में पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव में पार्टी के दोनों ही धड़ों के सामने खुद को असली शिवसेनाएँ सावित करने की चुनौती होगी। भले ही आयोग ने शिवे गुट को असली शिवसेना बताया है, लेकिन यह जनता को तय करना है कि वह किसे असली शिवसेना मानती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जहाँ सभी राजनीतिक दल पूरे जोर-शोर के साथ चुनावी में उत्तरे हैं। तो वहीं शिवसेना के विभाजन के बाद महाराष्ट्र में पहली बार हो रहे विधायकों के सामने खुद को असली शिवसेनाएँ सावित करने की चुनौती होगी। हालांकि, इसके बाद सभी राजनीतिक दलों के बाद से पीसीसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अनुसार, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पीसीसी की संपूर्ण राज्य इकाइयों, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक कांग्रेस समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव के सी विषयोंपाल द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में उल्लेख किया गया है कि यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस कदम को पार्टी की हिमाचल इकाई के पुर्णगठन की कांग्रेस की योजना के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। पहाड़ी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से पीसीसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

हिमाचल कांग्रेस गुटबाजी से त्रस्त है, जो फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान देखी गई थी, जब तत्त्वालय कांग्रेस के उम्मीदवार अधिकारे संघीयी कुछ कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने और उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने के बाद भाजपा के हर्ष महाजनन से चुनाव हार गए थे।

महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को

किया अवैध रूप से गिरफ्तार, HC ने 2 लाख

का मुआवजा देने का दिया आदेश

एजेंसी।

27 जून, 2024 को हिंगोली के सिटी पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर को रह करने की याचिका के बाद जस्टिस विभाक नवनाड़ी और एसजी चपलगांवकर ने मामले की सुनवाई की। एफआईआर में मानहानि का आरोप लगाया गया और धारा 66-ए (आपत्तिजनक सामग्री भेजना) और 66-बी का हवाला दिया गया। (चोरी हुए कंप्यूटर को अपने पास रखना) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत। हालांकि, अदालत ने कहा कि धारा 66-ए को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना था, जबकि धारा 66-बी मामले के लिए अप्रासांकिक थी।

वैष्णवी हाई कोर्ट की

आरोपावाद पीठ ने महाराष्ट्र

के एसजी चपलगांवकर

को असंवैधानिक माना था, जबकि धारा 66-बी मामले को एक व्यक्ति को

अवैध रूप से

गिरफ्तार करने के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मामले में शिकायतकर्ता एक पुलिस

संपादकीय

तेल की धार जारी है मार

अभी—अभी कमर्शियल गैस कनेक्शन की कीमतों में 62 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि कर दी गई है। सरकार इस बात की बार—बार दुहाई दे रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तधि थिए हैं।

2014 में जब सरकार ने तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि की थी और पेट्रोल 59 रुपये प्रति लीटर से उच्चतरे उच्चतरे 108 रुपये तक पहुंचा था, तब बार—बार सरकार यह बताती थी कि तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं। जैसे—जैसे दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती हैं वैसे—वैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना सरकार की मजबूरी है। यह नीति मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने तब बनाई थी जब कच्चा तेल 120 डालर प्रति बैरेल पर घूम रहा था और कीमतों के दबाव से बचने के लिए उन्होंने आइल पूल डिफिसिट फड़ बनाया था वह बाजार के उत्तर—चढ़ाव को एव्हार्व करता था। इसीलिये कच्चा तेल 124 डालर होने के बावजूद पेट्रोल 58—59 रुपये लीटर मिल रहा था।

अभी—अभी मोदी सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी कई तथ्यों के साथ समझे आए हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि देश ने जैव ईंधन यानि एथेनाल के मिश्रण से लगभग एक लाख 6 हजार करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाई है विचारणीय है कि

मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने जब एथेनाल नीति बनाई थी तो उसका आशय यही था कि आयात निर्भरता घटाकर आम उपभोक्ता को लाभ पहुंचाया जाये। वर्ष 2014 तक मिश्रित ईंधन की कैलोरिक गुणवत्ता प्रायोगिक और शुरुआती दौर में थी। अतः एथेनाल का प्रयोग पेट्रोल की कुल खपत का 1.52 फीसदी तक ही था। यह खपत अन्तर 2023—24 में कुल खपत के 15 फीसदी तक पहुंच गई है। लेकिन इस बचत का लाभ न तो उपभोक्ता को ही हो रहा है तो ही आयात निर्भरता में इंडिया 2014 में हमारी सकल घरेलू खपत के मुकाबले आयात निर्भरता लगभग 70 फीसदी थी जो अब बढ़कर बैकॉल मंत्री हरदीप सिंह के 88 फीसदी पर पहुंच चुकी है। इसे नौ दिन बाले अंडाई कोस ही कहा जा सकता है। | क्योंकि अगर नीतियां सात—आठ साल में भी परिणाम न दें तो उनकी समीक्षा लाजिम हो जाती है।

इनवर्स्टमेंट इनफार्मेशन एड क्रेडिट कंपनी (ईक्रा) की रिपोर्ट बताती है कि कच्चे तेल की कीमतें 12 फीसदी कम हुई है। रूप से ने हमें बाजार से सस्ता कूड़ आइल देकर विगत तीन साल से निहाल किया है।

इसका लाभ न तो उपभोक्ता को मिला न ही अर्थव्यवस्था को विभिन्न तकनीकी अनुमान बताते हैं कि अगर एक डालर प्रति बैरेल कच्चे तेल की कीमत घटती है तो कंपनियों को 13 हजार करोड़ की बचत होती है। | कच्चा तेल 84 डालर प्रति बैरेल से घटकर 72 डालर पर आ गया है यानि 12 डालर प्रति बैरेल कीमतें गिर गई हैं। | जबकि

एक सरकारी आंकड़े के अनुसार मार्च से अब तक 15 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 12 रुपये प्रति लीटर डीजल पर मुनाफा बढ़ गया है। 160 हजार करोड़ की आयात बिल में बचत हुई है। 1544 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आयी है। देशी सरकारी कंपनियों इंडियन आइल को 39 हजार 619 करोड़ भारत परियोगियम को 26 हजार 673 करोड़ एवं दिनांकन पेट्रोलियम को 14 हजार 694 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अगर इसी अनुपात में कीमतें भी घटती तो परिवहन कार्पोरेट कम से कम 20 फीसदी नीचे आ जाती। परिवहन घटाना तो उत्पादन की कीमतें घटती मंहगाई नीचे आ जाती। आम नागरिक के जैब में पैसा बचता तो आर्थिक गतिविधियां तेज होती खपत बढ़ती और इस मुनाफा की खुशी भारत के आम व्यक्ति के चेहरे पर भी झलकती। तेल की कीमतों की बाजार से संबद्धता की नीति भी केवल जुमाना साबित हुई है। करोड़ों उभोकाऊं कूड़ आइल की बढ़ती कीमतों के दौर में से सरकार और कंपनियों का साथ दिया है लेकिन कंपनियों घटती कीमतों के दौर में जनता का साथ देने से बच रही है। जब पतली है तेल की धारा तो क्यों जारी है मार ...!!

न शर्म न ह्या संविधान की रोज ह्या ?

भारतीय आजादी के इस हीरक वर्ष में कभी शविष्यगुरुच का दर्जा प्राप्त राजनारा देश अब किसी का शशिष्य बनने के काबिल भी नहीं रहा है, यद्यपि हमारे भाग्यवान उत्तराखण्ड नेता विश्वभर में जाकर अपनी खुद की प्रशंसन करते रहे थक्के तो उत्तराखण्ड नेता विश्वभर में हमारी शिथित उस मयूर जैसी है जो प्रगति के बादल देखकर अनवरत नाचता है और उपलब्धि के अभाव में बाद में आंसू बहाता है।

आजादी के बाद से हमारे देश में भी राजनीति के अलग—अलग दोर रहे हैं, जवाहरलाल के जमाने की राजनीति प्रगति की कल्पना पर आधारित थी तो इंदिरा जी के जमाने से सत्ता के लिए सब कुछ करने की राजनीति का दौर शुरू हो गया और उन्होंने अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए आपातकाल जैसा कदम उठाया, किंतु आज की राजनीति उसे भी आगे निकल गई है और आज कुर्सी के खतिर संविधान को भी बख्ता नहीं जा रहा है और वह सब के लिए देखती है।

जलकिन सबसे बड़े असर्व की बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक सब कुछ बदला कितू राजनीताओं की सौच और मतदाता की समझ में कोई बदलाव नहीं आया। आज के राजनेता आजादी के पचहतर साल बाद भी चुनाव की उसी लीक पर चल रहे हैं जो प्रथम चुनाव के समय 1951 में देखी गई थी, आज भी राजनीति वादों और आश्वासनों पर टिकी है और आज के आम मतदाता को राजनेता उसी 1951 वाली नजर से ही देखते हैं और वैसा ही अहम करते हैं, कभी प्रगति और विकास के नाम पर चल रहे हैं।

जलकिन सबसे बड़े असर्व की बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक सब कुछ बदला कितू राजनीताओं की सौच और मतदाता की समझ में कोई बदलाव नहीं आया। आज के राजनेता आजादी के पचहतर साल बाद भी चुनाव की उसी लीक पर चल रहे हैं जो प्रथम चुनाव के समय 1951 में देखी गई थी, आज भी राजनीति वादों और आश्वासनों पर टिकी है और आज के आम मतदाता को राजनेता उसी 1951 वाली नजर से ही देखते हैं और वैसा ही अहम करते हैं, कभी प्रगति और विकास के नाम पर चल रहे हैं।

जलकिन सबसे बड़े असर्व की बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक सब कुछ बदला कितू राजनीताओं की सौच और मतदाता की समझ में कोई बदलाव नहीं आया। आज के राजनेता आजादी के पचहतर साल बाद भी चुनाव की उसी लीक पर चल रहे हैं जो प्रथम चुनाव के समय 1951 में देखी गई थी, आज भी राजनीति वादों और आश्वासनों पर टिकी है और आज के आम मतदाता को राजनेता उसी 1951 वाली नजर से ही देखते हैं और वैसा ही अहम करते हैं, कभी प्रगति और विकास के नाम पर चल रहे हैं।

जलकिन सबसे बड़े असर्व की बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक सब कुछ बदला कितू राजनीताओं की सौच और मतदाता की समझ में कोई बदलाव नहीं आया। आज के राजनेता आजादी के पचहतर साल बाद भी चुनाव की उसी लीक पर चल रहे हैं जो प्रथम चुनाव के समय 1951 में देखी गई थी, आज भी राजनीति वादों और आश्वासनों पर टिकी है और आज के आम मतदाता को राजनेता उसी 1951 वाली नजर से ही देखते हैं और वैसा ही अहम करते हैं, कभी प्रगति और विकास के नाम पर चल रहे हैं।

जलकिन सबसे बड़े असर्व की बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक सब कुछ बदला कितू राजनीताओं की सौच और मतदाता की समझ में कोई बदलाव नहीं आया। आज के राजनेता आजादी के पचहतर साल बाद भी चुनाव की उसी लीक पर चल रहे हैं जो प्रथम चुनाव के समय 1951 में देखी गई थी, आज भी राजनीति वादों और आश्वासनों पर टिकी है और आज के आम मतदाता को राजनेता उसी 1951 वाली नजर से ही देखते हैं और वैसा ही अहम करते हैं, कभी प्रगति और विकास के नाम पर चल रहे हैं।

जलकिन सबसे बड़े असर्व की बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक सब कुछ बदला कितू राजनीताओं की सौच और मतदाता की समझ में कोई बदलाव नहीं आया। आज के राजनेता आजादी के पचहतर साल बाद भी चुनाव की उसी लीक पर चल रहे हैं जो प्रथम चुनाव के समय 1951 में देखी गई थी, आज भी राजनीति वादों और आश्वासनों पर टिकी है और आज के आम मतदाता को राजनेता उसी 1951 वाली नजर से ही देखते हैं और वैसा ही अहम करते हैं, कभी प्रगति और विकास के नाम पर चल रहे हैं।

जलकिन सबसे बड़े असर्व की बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक सब कुछ बदला कितू राजनीताओं की सौच और मतदाता की समझ में कोई बदलाव नहीं आया। आज के राजनेता आजादी के पचहतर साल बाद भी चुनाव की उसी लीक पर चल रहे हैं जो प्रथम चुनाव के समय 1951 में देखी गई थी, आज भी राजनीति वादों और आश्वासनों पर टिकी है और आज के आम मतदाता को राजनेता उसी 1951 वाली नजर से ही देखते हैं और वैसा ही अहम करते हैं, कभी प्रगति और विकास के नाम पर चल रहे हैं।

जलकिन सबसे बड़े असर्व की बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक सब कुछ बदला कितू राजनीताओं की सौच और मतदाता की समझ में कोई बदलाव नहीं आया। आज के राजनेता आजादी के पचहतर साल बाद भी चुनाव की उसी लीक पर चल रहे हैं जो प्रथम चुनाव के समय 1951 में देखी गई थी, आज भी राजनीति वादों और आश्वासनों पर टिकी है और आज के आम मतदाता को राजनेता उसी 1951 वाली नजर से ही देखते हैं और वैसा ही अहम करते हैं, कभी प्रगति और विकास के नाम पर चल रहे हैं।

जलकिन सबसे बड़े असर्व की बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक सब कुछ बदला कितू राजनीताओं की सौच और मतदाता की समझ में कोई बदलाव नहीं आया। आज के राजनेता आजादी के पचहतर स

